duled Tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration in making appointments to Government services. This provision is supported by Article 16(4) which permits a State to make reservations in services for these classes.

In order to watch over the implementation of the various Constitutional safeguards, Article 338 has provided for the appointment of a Special Officer to investigate all matters relating to these safeguards. This Special Officer is known as the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and his Annual Reports are laid before Parliament and discussed.

As indicated earlier,—Government has been fulfilling all these Constitutional obligations. The Harijans from Haryana were arrested in Delhi not because they were protesting against eviction, but because they had violated prohibitary orders.

13.01 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 3rd December, 1973, will consist of:—

(1) Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

(2) Discussion on the Resolution seeking disapproval of the Central Excises and Salt (Amendment) Ordinance, 1973 and consideration and passing of the Central Excises and Salt (Amendment) Bill, 1973.

(3) Further consideration and passing of the Code of Criminal Procedure Bill, 1972 as passed by Rajya Sabha.

(4) Discussion on the 22nd Annual Report of the Union Public Service Commission.

(5) Consideration and passing of the following Bills as passed by Rajya Sabha:

(a) The Navy (Amendment) Bill, 1973.

(b) The Cinematograph (Second Amendment) Bill, 1973.

(c) The Prevention of Water Pollution Bill, 1969.

MR. SPEAKER: Please excuse me. I have to go and receive the British Delegation.

13.02 hrs.

[SHRI S. A. KADER *in the Chair*]

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): I request the Minister of Parliamentary Affairs to include a discussion on the inordinate delay in the establishment of the newsprint plant in Kerala. There is a national crisis due to newsprint shortage and the Government is very much concerned. The Hindustan Paper Corporation is going to establish the plant in Kerala in technical collaboration with NIDC. The Chairman of NIDC announced that the plant will come up in 1978 while the Minister said it will come up in 1976. The delegation of Hindustan Paper Corporation which went to Canada came back with much disappointment. There is a strong Canadian lobby under H. S. Siemens & Co. which is responsible for delaying the establishment of this project in Kerala. This delay means a loss of Rs. 28 crores in foreign exchange to the Government of India. So, this House must discuss this question. The Minister of Industrial Development must come forward with a statement that the plant will be established in time.

In Tamilnadu, the students have been attacked by hired goondas and the police did not give any protection. It is a serious matter. I know it is law and order, but the State Government has not maintained law and order. The CPM has been allowed to raise the law and order situation in West Bengal in this House. So, the

[Shri Vayalar Ravi]

Home Minister must come forward with a statement on this situation in Tamilnadu and we must have a discussion here.

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad): Sir, during this particular session, a number of important issues concerning the foreign policy of our country are taking place. We have had the honour of the visit of the distinguished general Secretary of the Communist Party of the Soviet Union, Mr. Brezhnev. A number of agreements have been signed. Apart from this, a number of news items and announcements have appeared in the press about the possibility of an Asian Collective Security System, to which a reference was made by the distinguished visitor in his Address to the MPs in the Central Hall yesterday. Then, the question of West Asia is also agitating our minds. It is a hot question. Our External Affairs Minister has said that India, as a leader of non-aligned countries, played an effective role at the UN with regard to the West Asian situation. This House should have an early opportunity—at least next week—to discuss some of these basic and important problems in regard to our foreign policy.

A week ago I had said that this House should have an opportunity of discussing the Fifth Five Year Plan. After this session started, a number of important announcements are appearing in the press that the Plan is being out or pruned etc. But this House has no chance to discuss these matters. I request that the Government should find time for a discussion on this next week. The discussion on the Approach Document which was inconclusive during the last session should be continued in this session as early as possible before we are told at the fag end of the session that the Plan is ready and we will discuss it in the budget session.

Lastly, because of the lockout in the Indian Airlines the pressure on the railways has increased. I would like the Minister of Railways to tell this House what special measures Government are taking to relieve th pressure on the railways so that the Railways carry more passengers until the lockout is lifted.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, बिहार में एक बहुत बड़ा संकट इन दिनों खास कर देहातों में उपस्थित है, उस की तरफ आप की मारफत पार्लियामेन्ट्री अफेअर्स मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि वे पैट्रोलियम मिनिस्टर से कह कर इस सम्बन्ध में एक बयान दिलवायें, साथ ही जो दिक्कत आज वहां के लोगों के सामने है, उस को देखें। वह दिक्कत है —कैरोसिन तेल की। वहां कैरोसिन तेल मिलना मुश्किल हो गया है। लोग अन्धेरे में रह रहे हैं। वहां बिजली की रोशनी नहीं है, खाना बनाने में दिक्कत होती है। तमाम लोग कोस रहे है कि यह क्या सरकार है—अन्धेरे में खाना बनाना पड़ता है, अन्धेरे में खाना पड़ता है। इस लिये मैं चाहूंगा कि इस के बारे में मंत्री जी बयान दें और साथ-साथ कार्यवाही करें ताकि वहां के लोगों को कैरोसिन तेल आसानी से मिल सके—खास कर देहातों में।

दूसरी बात—फूड कार्पोरेशन आफ़ इंण्डिया (भारतीय खाद्य निगम) के दर्जनों गल्ले के गोदाम बिहार में है। 1 नवम्बर से सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। जो गरीब उस की नौकरी पर जिन्दा थे, उन के सामने भुखमरी का सवाल पैदा हो गया है। हमारे पटना दीघा, फुलवारी—शरीफ, गया; कटिहार हर जगह उन के गोदाम है। सब जगह हंगामा मचा हुआ है। इन कर्मचारियों को हटाने की वजह से दुकानदारों को गल्ला ठीक से नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कृषि मंत्री इस के बारे में बयान दें और इस स्थिति का हल निकालने का प्रयत्न करें।

तीसरी बात—औद्योगिक विवाद कानून में परिवर्तन किया जाये—इस मांग को लेकर काफी शोर मचा हुआ है—मैडिकल सेल्ज रिप्रेजेंटेटिव और दूसरे लोग बहुत दिनों से आन्दोलन कर रहे हैं। बार बार मंत्रियों से मिल रहे हैं, प्रधान मंत्री जी से भी मिल चुके हैं लेकिन प्रधान मंत्री जी कहती है कि ये मैडिकल सेल्ज रिप्रेजेंटेटिव क्या हैं मैं चाहूंगा कि इन की बातों को सुन कर इस कानून में सरकार संशोधन करे और इन को भी वर्कमैन माना जाए और इसके अन्तर्गत जो सुविधायें दूसरे मजदूरों को मिलती हैं, वह इन को भी मिलें मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्री इस के बारे में बयान दें।

श्री मधु लिमये : (बांका) सभा पति महोदय, मैं चाहता हूं कि बैंक कमीशन की जो रिपोर्ट है उस के ऊपर अगले सप्ताह बहस करने का मौका इस सदन को मिले। मैं बहुत समय से इस बात को उठाता चला आ रहा हूं लेकिन सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बात यह है कि जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उन में से बैंक आफ महाराष्ट्र और खास कर सैंट्रल बैंक और दूसरे दो बैंक बड़े घाटे में चल रहे हैं।

सभापति महोदय, मैंने सुना है कि इस की जांच करने के लिए सैंट्रल बैंक ने एक कमेटी भी बैठायी है सामी पटेल के मामले में लाखों-करोड़ों रुपये का घाटा हुआ है, लेकिन आज सभी बैंकों की सर्प्लस-लिम्वीडिटी का सवाल आया है। बैंकों के द्वारा जो कर्जा दिया जाता है उसमें हेर-फेर होती है। मैं चाहूंगा कि अगले सप्ताह बैंक कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हो, जिस में इन सारी बातों का भी उल्लेख किया गया है, सिफारिशें की गई हैं —तो उसकी चर्चा करने का मौका हम को मिले।

दूसरी बात—क्योंकि महासचिव साहब ने आदेश दिया है इसी पर मैं बोलूं इसलिए एक दूसरा सवाल जिसका सम्बन्ध एक हरिजन की हत्या से है वह भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बिहार विधान सभा में हमारे दल के जो नेता हैं श्री कपिल देव सिंह उन्होंने मुझे को एक पत्र लिखा है वह पूरा पत्र तो मैं नहीं पढ़ता क्योंकि बड़ा लम्बा-चौड़ा है लेकिन उसके जो आवश्यक हिस्से हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कपिल देव जी अपने पत्र में लिखते है :

"30 अक्टूबर 1973 को सवेरे 7 से 8 बजे के बीच पटना मधुआ टोली कारपोरेशन आफिस के निकट से बड़हिया के अवधेश प्रसाद सिंह नामक जमींदार के लठैत तथा वे स्वयं (संख्या करीब दस) ने मंगल राम नामक एक गरीब हरिजन जाति (ढाढ़ी) को जबरदस्ती या जोप में उठा लिया और दिन भर अपने डेरा पटना में बांध कर रक्खा। मंगल राम के पिता का नाम परमेश्वर राम ग्राम फाजिल थाना बड़हिया है। उसकी पत्नी करीब 9 बजे जब कदम कुआं थाना गई तब दरोगा ने उसे बड़हिया जा कर पता लगाने को कहा। मंगल राम को शाम में लोग कार से बड़हिया ले गये जहां की दूरी 70 माइल की है। वहां ले जा कर उसे मार पीट किया और रात में करीब 2 बजे गंगा किनारे ले जा कर जिन्दा अवस्था में ही जला कर (पैट्रोल छिड़) फेंक दिया।

31 अक्तूबर को सवेरे मंगल राम का छोटा भाई कपिल देव सिंह विधायक के यहां गया। उससे सारी बातें सुनने पर उन्होंने उसका आवेदन-पत्र जो मुख्य मंत्री के नाम से था उसे उनकी अनुपस्थिति में मुख्य सचिव को दिया। इसकी जानकारी मुख्य मंत्री आई० जी० एस० पी० (पटना-मुंगेर दोनों) को

[श्री मधु लिमये]

दी गई । मंगल राम के पिता परमेश्वर राम ने पुलिस के सामने बयान भी दिया परन्तु आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इससे गरीब हरिजनों में क्षोभ है । मारने वाले एक 4 हजार बीघा जमीन के मालिक हैं। उनके बड़े बड़े लोग सम्बन्धी हैं ।"

सभापति महोदय मुझे यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि मुख्य मंत्री श्री अब्दुल गफूर वारन्ट निकालने के पक्ष में थे, शायद वारन्ट निकल भी गया था लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने पैरवी करके उस वारन्ट को खत्म करवाया ।

तो हम लोग बहुत लम्बी चौड़ी बातें करते हैं, अभी अभी ब्रेजनेव साहब आये थे ....

सभापति महोदय : लेकिन उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री मधु लिमये : उनसे गीत गवाने का काम किया गया था कि हम लोग बड़ी तरक्की कर रहे हैं । उनके सामने दूसरा पहलू थोड़े ही रखा गया था। दूसरा पहलू इसा है....

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : वे कोई हमारे मालिक थोड़े ही हैं।

श्री मधु लिमये : तो क्यों तारीफ़ करवाते हैं ? उनसे कहिये हमारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए ।

MR. CHAIRMAN: Please sit down. I would request Mr. Madhu Limaye to confine himself to relevant things. This is absolutely irrelevant. To say that we asked a foreign dignitary who had come on our invitation to India to praise us, as if we told him that he should praise us, I think, is not befitting this House or the Member speaking. (*Interruptions*)

श्री मधु लिमये : मैंने तो उस बारे में कुछ नहीं कहा । अगर आप चाहते हैं इस मुद्दे पर मैं कुछ न बोलूं तो आपके आदेश का मैं पालन करता हूं लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे देश में जो स्थिति है उसका यह जो काला पहलू है, दिन रात हरिजनों और आदिवासियों का मामला हम लोग यहां उठाते हैं, अभी दो दिन पहले 25–30 हजार का बड़ा जुलूस यहां पर आया था और उस समय हमने एडजर्नमेन्ट मोशन दिया था लेकिन आपने कहा यह मामला राज्यों के तहत आता है । कैसे आता है ? आप दफा 339 को देख लें, मैं एक ही हिस्सा उसका पढ़ना चाहता हूं :

"The executive power of the Union shall extend to the giving of directions to a State as to the drawing up and execution of schemes specified in the direction to be essential for welfare of the Scheduled Tribes in the State."

अब लोगों के वेलफेयर, लोगों के कल्याण के क्या मानी हैं ? अगर जान भी नहीं बचेगी तो लोक कल्याण के क्या होगा ? (**व्यवधान**) परलोक कल्याण होगा लेकिन मेरे जैसे लोग जो परलोक में विश्वास नहीं करते उनके लिए इस आशा पर इस सरकार को छोड़ देना बड़ा मुश्किल है । इसलिए मैं मानता हूं कि केन्द्रीय सरकार की इस में पूरी जिम्मेदारी है और अगर आप एडजर्नमेन्ट मोशन इस पर लाने के लिए तैयार नहीं हैं तो क्या आप रघुरामैया जी को आदेश देंगे कि इस की तत्काल जांच करायें ? उनके पास जितने जांच ब्यूरो आदि है, सी बी आई के लोग वहां जायें और मुख्य मंत्री को भी लिखा जाये । क्या वह व्यक्ति चार हजार बीघे का

जमीदार है इसलिए गिरफ्तार नहीं होगा ? उसने खुद जाकर बड़हिया में कहा था कि मैं ने बदला चुकाया है – शायद आपस में कोई झगड़ा हुआ था—और मैंने जाकर जिन्दा जलाया है; वे खुद कहते हैं और आपकी सरकार कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है । तो सरकार कब तक हरिजनों को ठगने का काम करती रहेगी ? सभापति महोदय, इसमें आपको भी कुछ कहना चाहिए क्योंकि एक हरिजन को जिन्दा जलाने का काम किया गया है । आप इसमें आदेश जारी कीजिये । बाद में एडजर्नमेन्ट मोशन के जरिए इस सरकार की निन्दा करने का मौका भी हमें मिलना चाहिए । (**व्यवधान**) .

यह एक मासूम बच्चे की तरह बात करते हैं । कानून तो बहुत सारे बनते हैं कानून में यह नहीं है कि काला बाजारी की जाये करों की चोरी की जाये या स्मगलिंग की जाये लेकिन वर्तमान व्यवस्था इतनी सड़ गई कि सारे गन्दे काम किये जाते हैं । (**व्यवधान**)

श्री रामावतार शास्त्री : बिहार में इनके दल के लोग भी इसमें शामिल हैं ।

श्री मधु लिमये : अगर आप नाम बतायेंगे तो उनको दल से निकाल देंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री : ठाकुर रमापति सिंह और वीर सिंह । (**व्यवधान**) वैसे जो बात आपने कही है मैं उसका समर्थन करता हूं । इस सम्बन्ध में बहस होनी चाहिए । वहां (चम्पारन) पर हर पार्टी के जमीदार कृषक संघ बनाकर, हरा झंडा लेकर खेतिहर मजदूरों और हरिजनों की हत्या कर रहे हैं । (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: I think, this is not the way to argue out.... (*Interruptions*)

श्री मधु लिमये : इस वक्त जो हमने विषय उठाया है उस पर कन्सेन्ट्रेट करना चाहिए और इस मसले को बाहर छेड़ना चाहिए । (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: I think, experienced members like Shri Madhu Limaye and Shri Ramavatar Shastri should not behave in this manner in the House. When I am on my legs, you should resume your seat.... (*Interruptions*)

अगर आप को चेयरमैन की बात नहीं सुननी है तो कैसे काम चलेगा ।

श्री मधु लिमये : मैं ने इन के बारे में कुछ नहीं कहा है ।

MR. CHAIRMAN आपको बीच में दखल नहीं देना चाहिये

Now if members are not interested, then I will adjourn the House for lunch. This is not the way that the business of the House should be conducted—including you Mr. Limaye and Mr. Ramavatar Shastri.

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : सभापति महोदय, सब से पहले मैं इस चीज की मांग करता हूं कि हरिजनों का जो बलिदान बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली हरियाणा में हुआ है, मैं चाहता हूं कि उस बहस जितनी जल्दी हो होनी चाहिये । अगर किसी की तरफ अत्याचार हुआ है तो हम कंडेम करेंगे पार्टी से ऊपर उठ कर । इसलिये इस विषय पर बहस हो ।

दूसरा सवाल यह है, आप को शायद मालूम है आज आप अपनी गाड़ी से आये होंगे लेकिन हम लोग टैक्सी से आये है, आज पूरी दिल्ली में नहीं बल्कि तमाम बड़े शहरों में टैक्सियों की हड़ताल है । और हड़ताल का कारण यह नहीं है कि वह किराया बढ़ाना चाहते हैं । वह चाहते हैं कि पैट्रोल के दाम घटें हमारी हमदर्दी उन के साथ है । मुझे ताज्जुब है मंत्री जी क्यों नहीं यहां आ कर स्टेटमेंट दे रहे हैं ?

तीसरा सवाल यह है कि श्रीराम इंस्टीट्यूट सितम्बर के महीने से बन्द पड़ा हुआ है । इस के बारे में माननीय सुब्रह्मण्यिम से कहा गया कि स्टेटमेंट दें, लेकिन वह भी नहीं

[श्री एस० एन० बनर्जी]

दिया गया। मुझे मालूम था कि श्रीराम का असर कांग्रेसी हुकूमत पर था, लेकिन उन के सुपुत्र चरत राम और भरत राम का भी असर सरकार पर है, यह मुझे नहीं मालूम था। अभी तक ब्यान नहीं दिया गया। जब कि उन्हों ने निकाला है कि 10 दिसम्बर तक अगर कर्मचारी वापस नहीं जायेंगे तो उन को नौकरी से निकाल दिया जायगा। इसलिये मेरी मांग है कि उस बारे में माननीय सुब्रह्मण्यम को एक ब्यान देना चाहिये। जब कि प्रधान मंत्री के पास हम ने लिख कर भेजा है कि इस की जांच होनी चाहिये। श्री राम इंस्टीट्यूट को टेक ओवर करना चाहिये इसलिये भरत राम और चरत राम से न डरते हुए मंत्री महोदय को यहां पर स्टेटमेंट देना चाहिये।

फूड कारपोरेशन में से 954 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। 770 उत्तर से। 55 दिल्ली से और 113 हरियाणा से फूड कारपोरेशन की बात सुनते हैं सारे देश में उन का विकास हो रहा है, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ सर्वनाश, यह बात कुछ समझ में नहीं आती। जैसा अभी एक मित्र ने कहा कि हरिजनों का वेलफेयर करना चाहिये, लेकिन यहां साथ साथ फेयरवैल कर रहे हैं। एफ०सी०आई० के बारे में माननीय वयालार रवि ने प्रश्न उठाया था, माननीय रामावतार शास्त्री ने उठाया, मैं चाहता हूं कि माननीय शिंदे साहब उस बारे में बयान दें कि जिस तरह से लोगों की छटनी की गई है आखिर उन का भविष्य क्या है? किस हैसियत से उन को नौकरी मिलेगी।

सभापति जी, आज के अखबारों में निकला है कि चीजों के दाम फिर बढ़ रहे हैं। और आप ने पढ़ा होगा :

"People in Delhi will find it hard even to wipe their tears. The prices of hand-kerchiefs have shot up by 125 per cent. The hand-kerchief which used to cost Re. 1 now costs Rs. 2.30."

हम लोग हैं डक चीफ के बगैर भी काम चला सकते हैं, हम पैंट से नहीं तो धोती से हाथ पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं :

"The sudden rise in the prices in the capital has also affected eggs, butter, mustard oil, pulses, cotton textiles and nylon yarn. No one can explain all these latest increased ranging from 15 to over 100 per cent."

मैं कहना चाहता हूं कि जो फर्दर इनक्रीज हुआ है मंत्री महोदय स्टेटमेंट दें और हमें बतायें कि सरकार उस बारे में क्या करना चाहती है, वर्ना यह चीज फैलती जा रही है कि पार्लियामेंट में जितनी बहस करो उतने दाम और बढ़ जायेंगे। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। इसलिये चाहता हूं कि उस के बारे में बयान दिया जाय।

SHRI SAMAR GUHA (Contai): I want to draw the attention of the Government to the All-India strike of the taxi-drivers and taxi-owners. They are having a big demonstration before the Boat Club today. The situation has become terrible. Fifty per cent of the taxis are lying idle. The income of the taxi-drivers and taxi-owners,—I don't find the taxi-owners much, I speak more about the taxi-drivers—has come to such a stage that it is almost impossible for them to maintain their families. In this situation, the Government must give a serious thought to the question as to what are the causes for the sudden rise in the prices of crude oil. We have heard today that the supply from Iran has not stopped. Then why should there be such a sudden and steep rise? Not only the taxi-drivers are affected, the scooterists are affected. The Government, without introducing ration.....

MR. CHAIRMAN: You are going into too many details. You have referred to it. You want a discussion on this. That is all.

SHRI SAMAR GUHA: You have been patient with others. Kindly be also patient with me and bear with me for a little while, Sir. Today is the 30th of November and so many days have passed. The Government has not come out with any statement—reasonable statement—regarding the reasons that could be attributed for the sudden rise in prices. The words usd by one newspaper are: "Savage rise in prices." I ask the Government to make a statement particularly in relation to the taxi-drivers' strike today.

Another point which I wish to raise is this. Neither the Secretary nor the Speaker is here. I am trying to draw the attention of the Speaker and the Secretary for the last 7 days....

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Secretary-General.

SHRI SAMAR GUHA: Secretary-General. Calcutta and West Bengal people are without newspaper for the last ten days due to sudden rise of the price of the newspaper, English and Bengali. Hawkers have boycotted them; they are not getting proportionate increase of commission and the people are almost reluctant to buy them at higher cost.

Now I want to know this from the Government. If there is increase in the price of newsprint what would be the proportionate price of the newspaper? They should say about that. They should make a certain calculation, Sir. I want to draw the attention of the hon. Minister to this. I have been trying to raise a Calling-Attention Motion. I failed. I wanted to raise under Rule 377. I failed. The whole of West Bengal is suffering for the last 10 days, without a newspaper. I want to know from the Government whether the Government is going to make a statement, whether there will be any uniform price rise all over the country, or will there be any control over them. What is the matter? Can any newspaper in any State suddenly raise the price? This is a very serious matter. For the last ten days the whole of the people of West Bengal are without newspaper. (*Interruptions*). They are printing it, but there is no circulation. I ask the Government to come out with a statement whether they have any policy whatsoever in regard to determining the price of the newspaper or whether they have allowed them to increase the price unilaterally.

Sir, in today's papers we find that there is an abnormal supply of crude, of kerosene oil, of cement, of power and may be many other things to U.P., double, treble and perhaps four times.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) वह बहुगुणा हैं ।

SHRI SAMAR GUHA: उन के इतने गुण हो गये हैं और गुण से गुण बढ़ रहे हैं ।

This is a serious matter—this manpower oriented power is being abused in the whole system of our democratic elections. The Government must come out with a statement whereby they make it clear that democracy means that the principles of election are being followed.

Lastly, one point about the C.B.I. The C.B.I. has framed a charge made out against the former Chairman of the E.C.I. The word used by them is 'criminal conspiracy and corruption'. So, I want to know from the Government as to what steps they are going to take on the basis of the C.B.I's report against him and whether the Government is going to make a statement on this or not.

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, I would like the Minister to take note of a very important issue. There is a sharp conflict between the Centre and the Maharashtra Government on the question of Maharashtra Agricultural Land Bill passed about 1½ years back in the Maharashtra Assembly. There is a sharp conflict between them and the Centre. Day before yesterday, the Chief Minister himself said that there was a sharp difference and this difference has widened still further. Therefore, I say that a discussion must be arranged. The most important aspect of this issue is that though the

[Prof. Madhu Dandavate]

Bill had been adopted 1½ years back in the Assembly, because there are differences about the limit of ceiling on lands and on giving retrospective effect to this, that is, whether it should be from 26th September, 1970 or from 1960 and since transfers of lands have taken place in between and there is a difference between the Centre and the State Government in this regard, a statement is called for from the Minister of Agriculture.

The Business Advisory Committee has decided at one of its meeting that the recommendations of the Sugarcane Commission should be discussed here. The date for that has also to be fixed up. I have also pointed out to him that he should make a statement.

A very serious situation has developed in Super Bazaar, at Delhi where 1500 quintals of wheat have been destroyed and 1500 quintals more are likely to be destroyed. The Civil Supplies Department has taken a very wrong attitude, I should say, bureaucratic attitude in this regard. I have furnished to the hon. Minister all the details as desired by him so that he would be able to make his statement. That statement also should come forward from him.

In the end I would like to make a mention about the burning issue created as a result of Shri Brezhnev's visit here; that is, about the 15 years economic cooperation declaration or collective security system which is proposed. This poses a problem for a wider alignment or dealignment for us. In this our attitude to China and other neighbours has also to be brought into the picture. It was suggested that the hon. Minister for External Affairs should make a statement.

Lastly, about the atrocities committed on Harijans. On this a discussion should be arranged. These are the few things I wanted to make.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta—North east): Mr. Chairman, Sir, I would like to reinforce the request already made for a discussion in the House on the reported atrocities recently committed on Harijans in different parts of the country, in Bihar, U.P. and elsewhere, and for this there should be a certain date and time allotted.

I also submit that we should have a discussion on international affairs, particularly, in view of the analysis of the world situation which we have heard yesterday. We have to give our views in regard to the world situation. I know, the Minister for External Affairs is ready to have this discussion as soon as ever it is possible for which with the Minister of Parliamentary Affairs' cooperation, perhaps, time will be found.

The third thing which I wish to suggest is that while for next week, the Cinematograph Bill was passed by Rajya Sabha is coming before the House, there is another Bill which is more important from the point of view of the workers in the film industry, which had been put before the House some eighteen months ago, I think it was in the autumn session of last year, which was withdrawn, because the hon. Minister suggested that it would have to be reformulated, but the reformulation does not seem to have been completed so far. Last session, in the other House, the Minister of Information and Broadcasting announced that he was going to introduce that Bill in this session in Parliament, but we have heard nothing about that Bill relative to the conditions of work of those who actually operate in the cinema industry, in the production, in the exhibition and in the distribution sections of the cinema industry. I suggest, therefore, that the conclusion of the discussion on the Cinematograph Bill should be supplemented without delay by the introduction of the other Bill which requires to be passed, particularly in view of Government's assurance which is now nearly more than two years old in regard to that legislation.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): I want to draw the attention of Government to a harrowing tale which I received regarding the atrocities that are

being perpetrated on the workers of the Patel Engineering Co. at Nahan in Himachal Pradesh. 1,300 workers have been thrown out of employment. The Patel Engineering Co. had been given the contract to finish the Jamuna hydel project, which comes under the UP Government but which had been financed by the Central Government, within a certain time-limit. Since they could not do so, they have created a situation there and they have declared a lock-out, and taking the help of the police there, they are adopting all sorts of heinous methods to suppress the workers. An advocate who is conducting the cases of these workers....

MR. CHAIRMAN: Let him not go into the details. Let him say that he wants a discussion on this matter.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: It is a serious thing. It is not merely a question of the lock-out. So, kindly hear me. Mr. Jagjit Singh Negi who is an advocate has been arrested by the Himachal Pradesh police because he is defending the case of the workers. Another advocate, Mrs. Shyama Sharma, who is the only lady advocate in Himachal Pradesh, who is also defending the workers is missing; a warrant has been issued against her, and her parents are frantically telling us that nowhere could she be traced and they are apprehending that she has already been kidnapped. That is what the people are talking there. Firstly, this lock-out is *mala fide*.....

MR. CHAIRMAN: Let him not go into those details. Let him merely say that this matter should be discussed or that a discussion on this is necessary.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Government must come forward with a statement about why this lock-out is there in the Jamuna hydel project being executed by the Patel Engineering Co., and why there is repression by the Himachal Pradesh police especially by the Superintendent of Police of the district. Is it a fact that the same superintendent is in league with or is connected with the Chief Minister who comes from the same district also?

My question relates to two things. The first is regarding the lock-out, and the other is regarding the police repression even on the legal practitioners, not only on the workers but even on the legal practitioners or advocates who are taking up their cases in the court.

It is also reported that several times, lathi charges were made by the police there as a result of which two workers died, and an MLA of the area, Mr. Tulsi Ram has also been arrested and is now in jail. No legal protection is given. Anybody who comes forward to defend him is arrested. As for persons who were lathi-charged as a result of which some people received serious injuries—Shri Tulsi Ram also received injuries—no medical relief was given to them.

MR. CHAIRMAN: You want an overall discussion.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Yes, on this issue.

The next point is regarding a matter already raised by Prof. Mukerjee regarding the treatment of prisoners in W. Bengal jails, in all jails. Even beating and killing is going on in the jails. Besides, the demand of political prisoners for corresponding treatment is not conceded. Persons arrested and kept in police lock-up and in jail are severely beaten. This complaint has been there for days together. But nothing is done. So Government must come forward with a statement clarifying their policy as Prof. Mukerjee has put it. Do they want a uniform method or rule for treatment of prisoners in jails all over the country, specially those connected with political activities? Political prisoners should be given political status. Recently, we know that 40,000 people were arrested for protesting against the price rise. No political status was given to them.

MR. CHAIRMAN: Please do not argue. Say what you want.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: We want a discussion here. The concerned Minister should come forward and

state here and now that the persons who are arrested or will be arrested on political grounds will be given political status whether it is in West Bengal or any other State. This should be done. I want to remined the hon. Minister of Parliamentary Affairs to arange some time for a discussion on this also.

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से संसद् कार्य मंत्री को निवेदन करूंगा कि वह इन विषयों पर चर्चा करवायें।

इस सदन में खाद्य निगम की रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिए। विजिनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस को स्वीकार कर लिया है। मंत्री महोदय यह चर्चा कब करवाने वाले हैं? इस में जो नाना प्रकार की गड़बड़ियां चल रही हैं, उन पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। वहां पर जो छटनी हो रही है, उस को रोका जाय और जिन लोगों की छटनी की गई है, उन को काम पर रखा जाय।

मोदी नगर में मोदी उद्योग के मालिक हर साल दो चार मर्डर करवाते रहते हैं। यह उन का नियम बन गया है। जो कोई भी उन के खिलाफ कोई बात उठाये या मजदूरों की कोई मांग लेकर उन के पास जाये, तो उस का मर्डर करवा दिया जाता है। उन के यहां जो एक सुभाष शर्मा नाम का एक स्टोनोग्राफर था। उस ने एक यूनियन बनाई। जब उस को ऐसा करने से मना किया गया तो वह नहीं माना। परसों की घटना है कि मोदी साहब ने अपने पांच छः आदमियों को बारह बजे एक जीप में उस के घर भेजा। उन लोगों ने अपने चहरे ढके हुए थे। उन लोगों ने सुभाष शर्मा को जीप में बिठा लिया और उसका मर्डर करने के लिए जंगल की तरफ ले गये। वह चिल्ला रहा था। रास्ते में रेल का फाटक बन्द था। लोगों ने दो आदमियों को पकड़ लिया और उन को जीप के साथ थाने में ले गये। बाकी लोग भाग निकले। वहां पर मोदी साहब का इतना प्रभाव है कि वहां का कलक्टर तहसीलदार और पुलिस उन की खरीदी हुई है। उन्होंने पुलिस थाने में फोन किया और तब जीप और उस के ड्राईवर को छोड दिया गया। इस घटना को लेकर मोदीनगर के सारे उद्योग चार पांच दिन से बन्द हैं और वह हड़ताल चल रही है। लेकिन समाचार पत्रों में इस बारे में कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ है, क्योंकि वहां के पत्रकारों को भी खरीद लिया गया है। मोदी साहब के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इस लिए इन घटनाओं पर इस सदन में चर्चा होनी चाहिए।

आप को याद होगा कि पिछली बार इस सदन में हमारे दल के सदस्य, श्री फुल चंद वर्मा, हिमाचल प्रदेश के नाहन नगर में एक हरिजन लड़की, कमलेश, के साथ बलात्कार का प्रश्न उठाया था। कान्ग्रेस के एक कार्यकर्ता ने जिस को स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिलती है उस लड़की के साथ बलात्कार किया।

श्री मूल चन्द डागा (पाली): ब्रह्मचारी को बलात्कार से क्या सम्बध है?।

श्री हुकम चन्द कछवाय: आप के लोगों ने किया है।

वह लड़की, और उसका पिता और एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष से मिले हैं। उन की जान खतरे में है। पुलिस सारे तथ्यों को मिटाना चाहती है मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री इस घटना के बारे में वक्तव्य दें और इसकी जांच करवायें अपराधियों को तुरन्त पकड़ा जाये और उन्हें दंड दिया जाये, वर्ना वे भाग जायेंगे। लड़की, उस के पिता, और उस सामाजिक कार्यकर्ता की, जिस ने यह केस पकड़वया, मर्डर करने के प्रयत्न हो रहे हैं। जो उस लड़की का अपहरण किया गया, तो उसकी मां और दादा उसके सदमें से मर गये। इस घटना के कारण

सारे नगर में उत्तेजना फैली हुई है । उस लड़की को देवी बता कर उस के नाम से अस्सी हजार रुपये इकट्ठे किये गये हैं । इन सब तथ्यों की जांच होनी चाहिए ।

SHRI B. V. NAIK (Kanara): May I make a submission under rule 295? This rule says that at any time after the report has been presented to the House a motion may be moved that the House agrees or agrees with amendments or disagrees with the report. Under this rule there is provision for half an hour's discussion on the report of the Business Advisory Committee, subject to the condition that there shall be a limit of five minutes for each Member. Substantial points have been made both in respect of the discussion on the Plan which is overdue since the plan draft is ready, we are told....

MR. CHAIRMAN: You have referred to rule 295. You cannot make a statement. Please confine yourself to your point of order. I am also to give a ruling on that.

SHRI B. V. NAIK: We have hardly three weeks' time. Unless these matters of topical interest like the Asian Collective Security as well as the draft Plan are taken up immediately, we will find ourselves faced with a situation similar to the one with which we were faced at the last session; some of these were guillotined.

MR. CHAIRMAN: I am sorry you are misusing the opportunity. Are you serious about your point of order?

SHRI B. V. NAIK: I am absolutely serious. Why is my credibility in doubt?

MR. CHAIRMAN: Uuder rule 295 the subject-matter is the report. This is not the report which is being discussed; this is a statement by the Minister of Parliamentary Affairs about the business of the House for the next week. Therefore it does not hold good.

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: I am grateful to the hon. Members for the very valuable suggestions they have made. Before I refer to two or three important points, I may submit that all the points to the extent they are relevant to the Central Government, will be considered by the Minister concerned. Two or three hon. Members raised the question about a discussion on international situation. I shall certainly communicate the desire of the House to the Minister of Foreign Affairs. The Food Corporation discussion, I think will be taken up in the week after next. That is what I understand. Discussion regarding Harijans can be held we are going to provide for a discussion on the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, later during this session. Anyhow that is a matter for consideration. About planning, I did mention last time and I also mentioned it to the Business Advisory Committee that the Planning Minister had informed that he would be laying the draft plan on the Table of the House during this session. Therefore, I represented to the Business Advisory Committee, how far it would be useful or fruitful to have a discussion on the Approach Document I shall again place it before the BAC for guidance. As I said, in all the other matters, I shall faithfullly convey to the Ministers concerned the various suggestions that have been made.

SHRI SAMAR GUHA: When will the Indo-Soviet Joint Communique be laid on the Table of the House?

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: About the documents mentioned by Shri Guha, I understand that the copies of the various agreements will be laid on the Table during the day some time before the House raises. I will confirm it.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Behar) : Last session, the discussion on the plan was adjourned. I would like to know whether it is necessary to refer this matter again to the Business Advisory Committee, because it is an adjourned discussion and it must have taken place in the first week itself.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : सभापति जी, मैं दो मिनट आपका चाहता हूं। यह एक प्रोप्राइटी का सवाल है । कल एक विदेशी महमान का हमने सैन्ट्रल हाल में स्वागत किया । यद्यपि वह सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सैक्रेटरी हैं फिर भी हमने उन्हें एक हैड आफ दी स्टेट का डर्जा दिया। हम ने उन्हे बड़ी इज्जत दी । मुझे यह देख कर बडा दुख हुआ कि सैन्ट्रल हाल में बैठने का जो इंतजाम किया गया था उस में इस सदन के एक सदस्य डा० शंकर दयाल शर्मा को पहली रो में बैठने के लिए कहा गया । डा० शंकर दयाल शर्मा रूलिंग पार्टी के प्रेसीडन्ट हैं । हम उनकी इज्जत करते हैं । लेकिन पार्लियामैंट में उनका कोई दर्जा नहीं है । वहां ए० पी० शर्मा भी बैठे थे, वह डिप्टी लिडर हैं, मैं समझ सकता हूं श्री हाथी भी बैठे थे, उन की बात भी मेरी समझ में आती है । लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रेसीडैन्ट को सैन्ट्रल हाल में होने वाले किसी भी समारोह में पहली रो में कैसे बैठाया जा सकता है ? मैं समझता हूं जो कुछ कल हुआ वह ठीक नहीं हुआ था और आप हमारी भावनायें स्पीकर साहब तक पहुंचा दें ।

DR. HENRY AUSTIN (Ernakulam): Sir, I always respect the views of Shri Vajpayee. Yesterday I had noticed that the leaders of the opposition parties were given seats on the front row. Dr. Shankar Dayal Sharma is the leader of the ruling party.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Not in Parliament.

DR. HENRY AUSTIN: Mr. Brezhnev is the leader of the ruling party there. Dr. Shankar Dayal Sharma is the leader of the ruling party here, and naturally he should be given a seat along with other party leaders. If he was not given a seat in the front row, what would Mr. Brezhnev think? Would he not think that the leader of the ruling party here has not been given a seat in the front row? I am sorry Mr. Vajpayee should have raised this point here.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, माफ कीजिए, देखिए इन्होंने बहस शुरू कर दी । डा० शंकर दयाल शर्मा पार्लियामैन्ट में कांग्रेस पार्टी के लीडर नहीं है । बाहर वह कांग्रेस पार्टी के लिडर हैं । अगर वह पार्लियामैन्ट में कांग्रेस पार्टी के लीडर होते तो प्रइम मिनिस्टर होते ।

MR. CHAIRMAN: The House will now adjourn and re-assemble at 3 P.M.

13.53 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fifteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at two Minutes past Fifteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now take up Private Members' Business. Shri Madhu Limaye to introduce his Bill.

15.02 hrs.

UNTOUCHABILITY (OFFENCES) AMENDMENT BILL*

[AMENDMENT OF SECTIONS 2, 9 ETC.]

श्री मधु लिमये (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति चाहता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Untouchability (Offences) Act,1955".

The motion was adopted.

श्री मधु लिमये : मैं विधेयक पेश करता हूं ।

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 30.11.73